VAID’S ICS LUCKNOW

**Daily Answer Writing Programme (DAWP):**

**Topics-Editorials from the Hindu/The Indian express/ET**

**(27/ 12/2023)**

**प्र. "उच्च शिक्षा प्रणाली की संरचना और शासन में बड़े सुधार की आवश्यकता है"। चर्चा करें । 250 शब्द**

शिक्षा वह अग्रणी क्षेत्र है जिस पर राष्ट्र के भविष्य को आकार देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

उच्च शिक्षा के लक्ष्य, किसी भी देश की किसी भी शिक्षा प्रणाली का समावेशन के साथ विस्तार, गुणवत्ता और प्रासंगिक शिक्षा सुनिश्चित करना है।

 

सरकार ने उच्च शिक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न पहल की हैं।

 NEP/राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), ज्ञान, इम्प्रिंट, स्वयं, उच्चतर अविष्कार अभियान, उन्नत भारत अभियान आदि। **(उन्हें संक्षेप में समझाएं)**

**चुनौतियाँ:**

1. वर्तमान में, भारत के अधिकांश विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा, नवीन विचारों के लिए अनुसंधान और नवीन कौशल के शिक्षा मानक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अनुरूप नहीं हैं।

2. शिक्षा और रोजगार योग्यता के बीच अंतर बढ़ रहा है। कई औद्योगिक व्यक्तियों ने कॉलेजों से आने वाले छात्रों की गुणवत्ता के बारे में शिकायत की। अधिकांशतः छात्रों में कार्य कौशल की कमी होती है।

3. हाल के अध्ययनों के अनुसार, कॉलेजों में लगभग 50% फैकल्टी अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं। लंबी अवधि में, अनुबंध संकाय के साथ पढ़ाने से गुणवत्ता और अनुसंधान पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

4. कई निजी कॉलेजों को यूजीसी से फंड और राज्य सरकारों से फीस रिफंड मिलना शुरू हो गया। खासतौर पर दक्षिण भारत में हर साल इंजीनियरिंग में काफी सीटें खाली रहती थीं। नए कॉलेजों और मौजूदा कॉलेजों की अनुमतियों के लिए वर्तमान की तुलना में अधिक जांच की आवश्यकता होती है।

**आगे बढ़ने का रास्ता:**

* विविध संसाधनों से नाटकीय रूप से बढ़ी हुई फंडिंग और एक नए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए एनईपी की सिफारिश इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।
* माध्यमिक शिक्षा के बाद की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन गुणवत्ता और सामर्थ्य दोनों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने के साथ, और डिग्री पूरा करने की बेहतर दर के साथ।
* "विश्व स्तरीय" अनुसंधान-गहन विश्वविद्यालयों को विकसित करना, ताकि यह सर्वोत्तम दिमागों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सके, शीर्ष अनुसंधान का उत्पादन कर सके और वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से संलग्न हो सके।
* यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी उच्च शिक्षा क्षेत्र जनता की भलाई के लिए काम करता है;
* विविध सामाजिक और शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संस्थानों के साथ एक विभेदित और एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणाली विकसित करना।
* संस्थागत स्तर पर स्वायत्तता और नवाचार की अनुमति देने के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालयों के प्रशासन में सुधार।
* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्च शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान में शामिल मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय।

**निष्कर्ष:**

इस प्रकार देश को उच्च शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए बेहतर बुनियादी ढांचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण/अनुसंधान और जवाबदेह शासन एवं नौकरशाही की आवश्यकता है।